18. डा० आर.वी. वैद्यानाथ अय्यर, अपर सचिव।

19. श्री आर० एस० पाण्डेय, संयुक्त सचिव (डी०पी०ई०पी०)।

20. श्री एस० सत्यमूर्ति, वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

2. इस समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:—

(I) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव संबंधी कानूनी, शैक्षिक प्रशासनिक और वित्तीय दिक्कतों की जांच करना और उन पर विचार करना।

(II) इस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उपयुक्त संवैधानिक तरीके सुझाना।

(III) सुविधाएं, जो प्रदान न की गई हों तथापि जिन्हें प्रदान करना न्याय-संगत है, को दर्शाने वाले दिशा निर्देशों का सुझाव देना।

3. समिति के अध्यक्ष को समिति के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए सदस्यों को सहयोजित करने तथा उपसमितियों के गठन के अधिकार प्राप्त होंगे।

4. आशा है कि समिति बैठक की अपनी रिपोर्ट पहली तारीख से दो माह की अवधि के भीतर ही प्रस्तुत कर देगी।

5. प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो समिति के कार्य के लिए आवश्यक कार्यालयीन सहायता प्रदान करेगा।

6. गैर-सरकारी सदस्य, सहयोजित सदस्य अथवा उप समिति के सदस्य भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ह०/-

(अतुल बगई)

उप सचिव (ई०ई०)

दूरभाष: 3387781

प्रतिलिपि सूचना और कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. समिति के सदस्य।

2. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव।

3. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा निदेशक।

4. आई.एफ.डी./स्थापना-I शिक्षा सचिव के वैयक्तिक सचिव।

5. शिक्षा सचिव, भारत सरकार।

Reports Relating to "State of Cooperation in India"

1610. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have received the reports on "State of Cooperation in india", submitted by Cooperative Initiative Panel;

(b) if so, the details of the important observations/recommendations made by the panel for taking new policy initiative for radical restructuring of Cooperative Institutions, State-wise;

(c) the reaction of the Union/State Governments thereto; and

(d) the present status in regard to the action taken, alogwith time schedule?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) The copies of reports on "State of Cooperation in India" published by the Cooperative Initiative Panel have been secured recently.

(b) The Panel in these reports have recommended to recognise the cooperatives as voluntary organisation formed by members based on the values enshrined in principles of cooperation, to amend the cooperative laws based on the recommendations of the Model Cooperatives Act, provide due priority to cooperative sector in the Plan document as an important sector of National economy and a clear State policy on Cooperatives. The Panel in its reports have made observations on action taken/urged to be taken by different State Governments on reformulation of their respective Cooperative Societies Acts.

(c) and (d) The thrust of the reports of the Panel is to reformulate the cooperative laws on the lines of Choudhary Brahm Perkash Committee Report. "Cooperative Societies" is a State subject and amendments in State Cooperative Societies Acts is within the legislative competence of the respective State Governments. However, it has been decided to replace the existing Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 on the lines of the recommendations made by Ch. Brahm Perkash Committee Report. It has also been decided to formulate a National Policy on Cooperatives.